

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 81/2021

उनवान

नाथु पिता डाईया पाटीदार जाति पाटीदार निवासी गोसाई का पारड़ा तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. नाथु पिता रणछोड पाटीदार जाति पाटीदार निवासी गोसाई का पारड़ा तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 06.8.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 228 रकबा 0.12 एयर भूमि वाके ग्राम गुसाई का पारड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उपरोक्त आराजी नम्बर की भूमि पर वादी का करीब 40 वर्षों से मकान बना होकर उसमें उसका खलिहान एवं पशुघर भी बना है व चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनी हुई है तथा उससे लगी हुई वादी की कृषि भूमि भी स्थित है। सन् 1985 में प्रार्थी को उपरोक्त भूमि के पट्टे भी सरकार द्वारा आवंटित किये गये हैं। वादी उक्त भूमि पर वर्षों से निवासरत होकर करीब 12 वर्षों से उसमें विद्युत कनेक्शन भी जुड़ा होकर इस मकान में वादी अपने परिवार के साथ निवासरत है। उक्त भूमि पर वादी का मकान स्थित होकर शेष भूमि पर वादी खलिहान के रूप में उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि मध्य आबादी में थी जिसे प्रतिवादीगण ने धोखे से राजस्व कर्मी, पटवारी, कानूनगो से मिलकर **At the Back of Party** मौके की स्थिति देखे बिना, भौतिक सत्यापन के अपने नाम आवंटित कर दर्ज रेकॉर्ड करवा ली जबकि वादी इस भूमि का एक मात्र अधिकारी होकर कब्जेदार है व करीब 40 वर्षों से अधिक पुराना मकान बना होकर उसमें निवासरत है तथा मकान से लगी हुई भूमि पर खलिहान व पशुघर के बाड़े के रूप में उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुस्तैनी मुखालफाना कब्जा है। जिस वजह से खातेदार घोषित होने हसब धारा 88 रा.का.आ. के तहत यह दावा पेश है। उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवंटित करवा दी है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर पुस्तैनी मकान, खलिहान, पशुघर बाड़ा के रूप में उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त सर्वे नम्बर की भूमि प्रार्थी/वादी की है। लेकिन बिना जानकारी दीए मिलीभगत कर राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण करवा दी है। जो कि विधि विरुद्ध होने से उक्त भूमि के प्रतिवादी के पक्ष में हुए सभी नामान्तरण स्वतः ही वादी के विरुद्ध प्रभावहीन व बेअसर होने से काबिल निरस्ती है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण यह भलीभांति जानते थे कि भविष्य में भी यह जमीन उन्हें नहीं मिल सकती जिस वजह से उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ने किसान ऋण प्राप्त कर उक्त भूमि यदि हाथ से चली भी जाए तो उनको नुकसान नहीं हो। प्रतिवादीगण अत्यन्त चालाक व अपराधी प्रवृत्ति के लोग होने से उक्त भूमि को खुद बुर्द कर सकते हैं। जिस वजह से धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा उक्त भूमि पर जारी किया जाना आवश्यक होने से वाद पेश है। वादी का वाद कारण उपरोक्त वर्णित भूमि वादी का अधिकारी के बिना **At the Back of Party** राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा दिया। जबकि प्रतिवादी को जानकारी में है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का पुस्तैनी मकान, खलियान, पशुघर व बाड़ा बना हुआ है। लेकिन विवाद उत्पन्न कर वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने से उक्त वाद

उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादी का वाद बहक विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री सादीर करना फरमावें कि -

(अ) वादी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 228 रकबा 0.12 एयर भूमि वाके ग्राम गुसाई का पारड़ा तहसील गढ़ी, में स्थित है, में वादी का एक मात्र पुश्तैनी हक कब्जा, स्वामित्व निरन्तर निर्बाध रूप से होने से वादी का मुखालफाना कब्जा होने से वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाने हेतु वाद पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत की जाने पर वादी स्वयं नाथु पिता डाईया पाटीदार की साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश होकर वादी अभिभाषक द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये जाने के पश्चात् वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श-1, मौजा गुसाई का पारड़ा के नक्शे की नकल प्रदर्श-2, विद्युत विभाग की रसीद प्रदर्श-3, विद्युत बिल प्रदर्श-4, पटवारी हल्का केसरपुरा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक अरथूना का मौका पर्चा दिनांक 25.11.2019 प्रदर्श-5, नकल तुलनात्मक प्रदर्श-6, मकान की रसीद प्रदर्श-7, नकल पर्चा नोटिस प्रदर्श-8, 9, 10 एवं नकल तुलनात्मक प्रदर्श-11 आदि का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी का आवासीय मकान एवं पशुघर प्रतिवादी नाथु पिता रणछोड़ पटेल की खातेदारी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.12 हे०, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.03 हे० भूमि पर बना हुआ है, जो कि प्रथम दृष्ट्या प्रत्यक्षतः प्रतिकूल कब्जे का प्रकरण है। वादी द्वारा प्रतिवादी के स्वामित्व की भूमि खाता संख्या 79 (नया) 57 (पुराना) के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.12 हे०, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.03 हे० भूमि के 1/2 हिस्से पर अवैध रूप से मकान/बाड़ा/पशुघर बनाकर कब्जा किया हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Petition For special Leave to appeal (CIVIL) No. 28034/2011 State of Haryana v/s. Mukesh & Others decision dated 30.9.2011 का संदर्भ इस न्यायालय द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय में प्रतिकूल कब्जे (Adverse possession) की खुलकर विवेचना की गई तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व/खातेदारी अधिकार के दावे की कठोर शब्दों में भर्त्सना की है। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि एक अतिक्रमी किसी वास्तविक मालिक की भूमि पर किसी तरह का निर्माण कर उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है जो कि एक तरह चोरी है। यह किसी के स्वामित्व की भूमि को बेईमानी से अपने नाम कराने का एक तरीका है। भूमि के मालिक/खातेदार की गलती से या लापरवाही से वह अपनी भूमि की निगरानी नहीं कर पाता है तो इसका लाभ उठाकर कोई भी अन्य व्यक्ति या अतिक्रमी उसे अपने नाम नहीं करवा सकता। S.M. Karim v/s. Bibi Sakina (AIR 1964 SC 1254) में भी यह स्वीकार किया है कि किसी भूमि पर लम्बा स्वामित्व यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिकूल कब्जा हों। Bhim singh & Others v/s. Zile singh & Others (AIR 2006 P & H 195) में भी माननीय न्यायालय ने यह माना है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही जा सकती।

यद्यपि प्रतिवादी नोटिस तामील होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, एक तरफा कार्यवाही की गई। एक तरफा कार्यवाही होने से तनकी भी नहीं बन सकी, लेकिन प्रतिवादी, जो कि विवादित भूमि का वास्तविक खातेदार है, के अनुपस्थित रहने या कोई जवाब नहीं देने मात्र से सिर्फ वादी के कब्जे के आधार पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर वास्तविक खातेदारी यानि प्रतिवादी को उसके खातेदारी अधिकारों से मात्र प्रतिकूल कब्जे के दावों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एक अतिक्रमी किसी वैध खातेदार/मालिक की भूमि पर कब्जा कर खातेदारी घोषणा का दावा करता है जो कि विधि द्वारा गलत कार्य माना गया है, ओर एक वैध खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त करना सही कैसे हो सकता है? इस संबंध में Karnataka Board of Wakf v/s. Govt. of India & Others में माननीय न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि "Non-use of the property by the owner even for a long time will not affect his title. But the position will be altered when another person takes possession of the property and

उपखण्ड अधिकारी  
ज.सी., जिला बांसवाड़



asserts a right over it. Adverse possession is a hostile possession by clearly asserting hostile title in denial of the title of the true owner" वादी द्वारा अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, वादी द्वारा नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श-1 प्रस्तुत किए, खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का ठोस, कानूनी आधार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी खसरा गिरदावरी को खातेदारी अधिकार लेने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। विद्युत बिल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं, विद्युत कनेक्शन वर्तमान समय में कोई भी ले सकता है, विद्युत कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क व दस्तावेज आवश्यक होते हैं, अतः यह कोई ठोस आधार नहीं है। मौका पर्चा प्रदर्श-5 में भी सिर्फ वादी के द्वारा निर्माण की गई संरचनाओं का ही उल्लेख है जो कि मौका पर्चा बनाते समय पटवारी को अपनी रिपोर्ट में मौके की स्थिति का उल्लेख करना होता है, यह भी कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विवेचना एवं मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि वादी ने प्रतिवादी की स्वामित्व वाली भूमि पर एक तरह से अवैध कब्जा कर रखा है, तथा इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-88 के तहत खातेदारी उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु धारा-188 में भी अनुतोष चाहा गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। यह एक तरह से किसी वैद्य/वास्तविक खातेदार को उसके स्वामित्व के अधिकारों से वंचित कर किसी अन्य अतिक्रमी को खातेदार बनाने का एक गलत तरीका है। साथ ही वादी ने अपने दावे को सिद्ध करने या समर्थन में पर्याप्त/संतोषजनक साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः वादी को चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी  
उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी को चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है। निर्णय आज दिनांक 06.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी  
उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या: 81/2021

## उंनवान

नाथु पिता डाईया पाटीदार जाति पाटीदार निवासी गोसाई का पारड़ा तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।

बनाम

—: वादी

1. नाथु पिता रणछोड पाटीदार जाति पाटीदार निवासी गोसाई का पारड़ा तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

—: प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी को चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही होने से वादी का वाद अस्वीकार कर वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिंग शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.8.2024 को जारी की गई।

दिनांक: 06.8.2024

(अन्जु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुदवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुकमनामा	शून्य
बबत इजराय हुकमनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा